दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 ▶ अंक : 9 ▶ गाजियाबाद, सितम्बर, 2020 ▶ मूल्य : 4 रूपया ▶ पृष्ठ : 04 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

सिटी फॉरेस्ट के लिए प्रस्तावित..P-4

कोरोना लाइव

4,069,522	3,146,135	70,168	26,892,380
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

सीमा पर भारी तनाव के बीच भारतीय सेना की दरियादिली, चीनी नागरिकों की बचाई जान

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में भले ही भारत और चीन के सैनिक आमने–सामने हो लेकिन लद्दाख और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद भारतीय सेना का मानवीय चेहरा सामने आया है। सेना के जवानों ने सिक्किम के दुर्गम क्षेत्र में रास्ता भटके एक महिला सहित तीन चीनी नागरिकों की जान बचायी और उन्हें जरूरी साजो सामान भी दिया। ये चीनी नागरिक उत्तरी सिक्किम के 17 हजार 500 फुट की ऊंचाई पर पठारी क्षेत्र में रास्ता भटक गये थे।

भारतीय सेना के जवानों ने जब इनकी जान को खतरे को महसूस किया तो इनकी सहायता के लिए मदद का हाथ बढाया। शून्य से भी कम तापमान में फंसे इन लोगों में दो पुरूष और एक महिला शामिल थी। जवान तत्काल वहां पहुंचे और उन्हें अत्यधिक ऊंचाई की परेशानियों तथा कठिन जलवायु स्थितियों से बचाने के लिए आक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़ों सहित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। जवानों ने उन्हें उनके गंतव्य पर पहुंचने के लिए समुचित दिशा–निर्देश दिये जिसके बाद वे वापस चले गए। चीनी नागरिकों ने उनकी त्वरित सहायता के लिए भारत तथा भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता जाहिर की।

- चीनी नागरिक उत्तरी सिक्किम के 17 हजार 500 फुट की ऊंचाई पर पठारी क्षेत्र में रास्ता भटक गये थे। भारतीय सेना के जवानों ने जब इनकी जान को खतरे को महसूस किया तो इनकी सहायता के लिए मदद का हाथ बढाया। शून्य से भी कम तापमान में फंसे इन लोगों में दो पुरूष और एक महिला शामिल थी।

गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच पिछले करीब चार महीने से गतिरोध चला आ रहा है जिससे सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मई के महीने में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर झड़प हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से गलवान में हिंसक झड़प हुई।

इस दौरान 20 सेना के जवान शहीद हो गए जबकि चीन के करीब 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि, चीन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा नहीं बताया। उसके बाद से लगातार कई दौर की बातचीत के बावजूद स्थित तनावपूर्ण बनी हुई है।

अब एक किसान को 50 बोरे से अधिक नहीं मिलेगी यूरिया

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। यूरिया की कालाबाजारी और किसानों द्वारा दुरूपयोग की आशंका के चलते अब यूरिया की ब्रिकी के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। भारत सरकार के पोर्टल पर डाली जाने वाली सूचनाओं की पहले जिलास्तरीय अधिकारी मॉनिटरिग करेंगे। किसानों की अब उसकी खेती योग्य भूमि के आधार पर ही यूरिया दिया जाएगा।

इसके लिए अब एक किसान को एक बार में केवल पांच और एक फसल के लिए अधिकतम 50 बोरे यूरिया ही दिया जाएगा। यूरिया वितरण को लेकर कृषि विभाग ने 22 बिदुओं की कार्ययोजना तैयार की थी। जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और कॉपरेटिव को इस सभी बिदुओं पर अमल करते हुए यूरिया ब्रिकी करवाने के आदेश दिए गए थे।

हाईटेक सिटी के नाम पर सरकारी खजाने को लगाई 1200 करोड़ की चपत

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के द्वारा प्राइवेट डवलपर्स के द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक सिटी के नाम पर सरकार के खजाने में करीब 1300 करोड की चपत लगा दी गई। बताते है कि सन सिटी समूह को 572 करोड तथा उप्पल चडडा समूह को 772 करोड का लाभ पहुंचाया गया। केग की प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद से जीडीए में हडकंप मच गया है। सूत्र बताते है कि कैग की रिपोर्ट के बाद बिल्डर और जीडीए के अनेक अफसर ईडी के रडार पर आ गए है। माना जा रहा है कि ईडी ने यदि बिल्डरों की कुंडली खंगालना आरंभ किया तो जीडीए के वह तमाम आला अधिकारी भी बेनकाब हो सकते है, जिनके द्वारा अपनी काली पूंजी बिल्डरों के प्रोजेक्ट में लगायी है। बताते है कि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि

- कैग की रिपोर्ट में खुलासा, उप्पल चड्डा समूह को पहुंचाया गया 772 करोड का लाभ
- विधान सभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद जीडीए में हडकंप
- जीडीए के अफसर और बिल्डर ईडी के रडार पर

हाईटेक टाउनशिप के लिए जिस जमीन को तय किया गया,उसका भू उपयाग कृषि था। बताते है कि 2006–07 के दौरान जो समय समय पर हाईटेक टाउनशिप की कडी में नीति तैयार हुई,उसमें भी बिल्डरों से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली की जानी थीं। सूत्र बताते है कि सन सिटी समूह से 572 करोड एवं उप्पल चडडा समूह से 772 करोड रूपए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के तौर पर सरकारी खजाने में जमा कराए जाने थे, लेकिन बताते है कि बिल्डरों से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क वसूल ही नहीं किया गया। अधिकारी उस वक्त पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे। पता चला कि कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ईडी हरकत में आ गई है तथा ईडी के निशाने पर बिल्डर और जीडीए के अधिकारी आ गए है।

माना जा रहा है कि ईडी के द्वारा यदि बिल्डरों के रिकार्ड खंगालने आरंभ किए तो जीडीए के वह तमाम अधिकारी भी कार्रवाई के घेरे में आ सकते है जिनके द्वारा काली पूंजी बिल्डरों के प्रोजेक्ट में लगा रखी है। बताते है कि प्रवर्तन विभाग में तैनाती के साथ अनेक अधिकारियों ने मोटा पैसा कमाया कि उसे बिल्डर प्रोजेक्ट में लगा रखा है। हालांकि जीडीए सचिव संतोष कुमार राय के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट को लेकर अनभिज्ञता जताते है।

रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 80 नई ट्रेनें, 10 सितंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन

नई दिल्ली। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे–धीरे पटरी पर उतरने लगी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर शुरू होगा। आपको बता दें कि इस समय करीब 230 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के संबंध में अधिसूचना दिन में बाद में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 80 नई विशेष ट्रेनें या 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होगा। ये ट्रेनें पहले से ही चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। यादव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, श्शविशेष ट्रेन के लिए जब भी जरूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की (क्लोन) ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सकें। यादव ने यह भी कहा कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिच. ालन करेगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभी केवल कोरा. ना स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने ये साफ नहीं किया है कि ये जो नई ट्रेनें चलेंगी ये कोरोना स्पेशल होंगी या फिर इनका नॉर्मल संचालन किया जाएगा। गौरतलब है कि कोविड 19 महामारी के कारण रेल यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। शारीरिक दूरी और स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। वातानुकूलित कोचों में चादर तकिये, कंबल आदि देना बंद कर दिया गया है। एसी का तापमान 25 डिग्री सेल्शियस रखा जा रहा है। पेंट्री भी बंद कर दी गई है। केवल पैक्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्रियों को स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच के बाद ही आने दिया जा रहा है। रेल यातायात को सामान्य शुरू करने के बारे में एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने कहा कि सामान्य यातायात बहाल करने के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नियमित गाड़ियों पर अगले आदेश तक रोक लागू है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

श्रम–जगत

E-mail : udyogviharnp@gmail.com   गाजियाबाद, सितम्बर, 2020

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING: U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES: ZONE-I	GUJRAT: ZONE-II	PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	MINIMUMWAGES			MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
W.E.F.	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA		BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8776.83	9024.24	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9556.83	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10453.83	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11485.83	11517.45	*

इंदिरापुरम में नहीं फैलेगा कूड़े से संक्रमण, नगर निगम ने तैयार की

कूड़े को जैविक तरीके से खत्म करने की योजना

- नए नगर आयुक्त आने के बाद से हरकत में आए अधिकारी
- शक्तिखंड के 35 हजार वर्ग मीटर खाली प्लॉट पर है कूड़े का पहाड़
- अब जैविक प्रक्रिया से कूड़ा खत्म करने को नगर निगम ने चयनित कर ली है कंपनी

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)– **गाजियाबाद।** इंदिरापुरम से जल्द ही कूड़े का ढेर हटने वाला है। आस–पास के लोगों को इससे फैलने वाले बदबू और संक्रमण से जल्द ही निजात मिलेगी। नव नियुक्त नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर अधिकारियों ने अब यहां जैविक प्रक्रिया से कूड़ा खत्म करने की योजना बनाई है। एनजीटी के आदेश पर शक्तिखंड के डंपिंग ग्राउंड के कूड़े की गंदगी को जल्द खत्म करने की प्रक्रिया को नगर निगम ने तेज कर दिया है।

बता दें कि लंबे समय से इंदिरा. पुरम के शक्तिखंड–4 स्थित करीब 35 हजार वर्ग मीटर में फैले प्लॉट पर लंबे समय से कूड़ा डंप किया जा रहा है। लंबे समय से यहां कूड़ा डंप होने से आस–पास की सोसायटियों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। इसी को लेकर कंफेडरेशन ऑफ ट्रांस हिंडन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पूर्व में एनजीटी में याचिका डाली गई थी। एनजीटी ने गत वर्ष ही नगर निगम को यहां से कूड़ा हटाने को निर्देशित किया था, जिसके बाद से भी कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया धीमी चल रही थी।

जब फेडरेशन पदाधिकारियों ने दुबारा इसकी शिकायत करने की बात कही तो निगम अधिकारी सचेत हुए हैं और अब यहां जैविक प्रक्रिया से कूड़ा खत्म करने की योजना बनाई गई है। अब यहां से कूड़ा हटाने में नगर निगम और जीडीए दोनो काम करेगा। दरअसल यहां जो भी कूड़ा एकत्रित है वह जीडीए कालोनियों से निकला हुआ है, ऐसे में कूड़ा निस्तारण का खर्च जीडीए द्वारा वहन किया जाएगा। नगर निगम के चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन ने बताया कि जल्द ही शक्तिखंड से कूड़ा हटा दिया जाएगा।

भाकियू के अल्टीमेटम पर 45 गांवो में सड़क बननी शुरू

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)– **गाजियाबाद।** मेरठ–दिल्ली एक्सप्रेस (डीएमई) वें पर निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही के चलतें प्रभावित गांवों की खराब हुई सडकों की अखिरकार जिला प्रशासन के दवाब के चलतें कंपनी के ठेकेदारो ने सुध ले ली है। बता दें कि भाकियू ने गत दिनों एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह को दिये गये ज्ञापन में चेताया था कि यदि गांवो की सडकों का निर्माण एक सितंबर से शुरू नही हुआ तो वे धरना प्रदर्शन कर डीएमई का काम रोक देंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह व जिला प्रभारी जय कुमार मलिक के नेतृत्व में किसान डीएमई निर्माण के दौरान डासना से लेकर भोजपुर तक प्रभावित गांवों की क्षतिग्रस्त हुई सड़को को बनवाने की मांग छरूमाह से महीनों से हाईवे की कंपनी से की जा रही थी। कंपनी लगातार टाल–मटोल करती आ रही थी। आक्रोशित किसानों ने दो सितंबर को धरना प्रदर्शन कर काम काज ठप्प कराने की चेतावनी दी थी। इससे दबाव में आकर कंपनी ने धरने से एक दिन पहले सड़कें बनाने का कार्य शुरू कर दिया। जिसे लेकर आज धरना देने पहुंचे किसानों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत होने के कारण शोकसभा आयोजित कर धरने को स्थगित कर दिया। डासना से मेरठ तक डासना, सिकरोड़, कुशलिया, चित्तौड़ा, नूरपुर, कलछीना, बड़ायला पट्टी भोजपुर अमराला मछरी फजलगढ़ पलोता, भडजन, लैहटा, चुड़ियाला सैदपुर मुरादाबाद काशी आदि सहित लगभग 40–45 गांवो के आवागमन के लिये सडक बनने का रास्ता साफ हो गया है। धरना प्रदर्शन करने आये राष्ट्कृपति प्रणव मुखर्जी को श्रंद्धाजलि देने वालो में जिला महासचिव राम अवतार त्यागी मंडल उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्यागी तहसील अध्यक्ष वेदपाल मुखिया भोजपुर ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष चौधरी श्यामवीर सिंह जिला सचिव चंद्र पहलवान जिला उपाध्यक्ष चौधरी पवन कुमार उर्फ लालाराम तहसील उपाध्यक्ष पप्पी नेहरा जिला सचिव संजय गुर्जर इरफान खान छोटे खान दीन मोहम्मद प्रधान चौधरी हरपाल पालमपुर जय गुर्जर विनय नगला विनोद मनोता दीपक मलिक लीलू सिंह चेयरमैन आदि लगे रहे।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Editorial

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, सितम्बर, 2020

सम्पादकीय

चीन को दो टूक

सत्येन्द्र सिंह

पूर्वी लद्दाख में भारत–चीन सीमा पर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए जारी सैन्य और कूटनीति स्तर की वाताओं का अब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है और ऐसे आसार भी नजर नहीं आ रहे कि आने वाले दिनों में वार्ता किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जाहिर है, चीन चाहता ही नहीं है कि सीमा पर किसी तरह की शांति बहाली हो, बल्कि जिस तरह से उसकी हमलावर गतिविधियां बढ़ी हैं और भारत के प्रति जो आक्रामक रुख अपना रखा है, उससे साफ है कि वह अब बड़े टकराव की तैयारी में है। इसलिए वह बार–बार भारत को उकसाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा इसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन अब भारत ने चीन को लेकर जो सख्त रुख दिखाया है, उससे यह साफ हो गया है कि चीन को उसकी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने चीन को एक बार फिर साफ–साफ कह दिया है कि शांति बहाली तभी संभव है, जब चीनी सैनिक पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से पीछे हट जाएंगे। भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जब तक सीमा पर पांच मई से पूर्व की स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक शांति बहाली की दिशा में बढ़ पाना संभव नहीं है। सच्चाई तो यही है कि चीन ने यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कार्रवाई करते हुए ताजा विवाद को जन्म दिया है। इसलिए जब तक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक गतिरोध दूर करने की दिशा में प्रगति की कोई उम्मीद नहीं है। भारत ने के कड़े रुख से साफ है कि वह अब चीन की किसी रणनीति के दबाव में नहीं आने वाला। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत की स्थिति अब 1962 वाली नहीं है। अब चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। चीन की तरह भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। रक्षा सेवाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत हाल में संकेत दे भी चुके हैं कि अगर चीन बातचीत से नहीं माना तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। थल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष का ताजा दौरा मजबूत सैन्य तैयारियों का संकेत है। अब ज्यादा बड़ा खतरा इसलिए भी है कि चीन और पाकिस्तान दोनों कभी भी एक साथ भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि भारत चीन और पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि का करारा जवाब दे। इस वक्त दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। चीन खुद भी इस समस्या से घिरा है। ऐसे में भी अगर वह पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को बढ़ा रहा है, तो साफ है कि वह दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करके उन्हें विवादित बनाने और अपनी सीमाओं का विस्तार करने की रणनीति पर चल रहा है। बेहतर होता इस वक्त चीन ऐसे सीमा विवादों के बजाय मानवीय रुख दिखाता। लेकिन उसे यह संकट एक बड़े अवसर के रूप में दिख रहा है। भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पहले उसे पीछे हटना होगा। लेकिन चीन इस बात पर अड़ा है कि वह फिंगर–4 क्षेत्र से अब तभी हटेगा, जब भारत भी समान दूरी तक पीछे हटे।

कोरोना का भय अब भयभीत नहीं करता, जिंदगी अब सामान्य होने लगी है

क्या अभी भी आप सबको कोरोना का डर सता रहा है? नहीं ना। शुरूआती दौर की अगर बात करें तो उस दौर के मुकाबले अब कोरोना से लड़ने के लिए हम सब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से ज्यादा तैयार हैं। कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? यह एक आमूलचूल परिवर्तन है। जिसमें इस महामारी को लेकर तमाम विशेषज्ञ वैज्ञानिक और शोध संस्थाएं पानी का घूंट पी पीकर आगाह कर रही थी, डरा रही थी, बता रही थी। वह आज हमारी जीवनशैली का सहज हिस्सा कैसे बन गया? कभी सोचा आपने। हम सब अपना हर काम कर रहे हैं। ऑफिस, नौकरी, कारोबार, घर का काम हो चाहे कैसा भी काम हो। सब सामान्य होने की ओर अग्रसर है। फर्क तो पड़ा है लेकिन जिस भयानक तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। स्वाइन फ्लू जैसी स्थिति बन जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। यहां तक कि खाने के लाले पड़ जाएंगे, निवाला तक लोगों को नसीब नहीं होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल मानव बहुत जीवट है। करोड़ों साल से सर्दी, गर्मी और बरसात इत्यादि को झेलता आ रहा है। इंसानी शरीर और उसका दिमाग इतनी सहजता से हार नहीं मानता। अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों ने डर की जो भयावह तस्वीर जनता के सामने दिखाई उसके पीछे अगर उनकी मंशा लोगों के बीच सतर्कता, सजगता और जागरूकता फैलाने की रही हो तो वह एक मामले में सही है लेकिन अगर सिर्फ डराने के लिए रही तो वह पूरी तरीके से गलत है।

सचेत करना अच्छी बात है लेकिन डराना गलत है। जिस तरीके से बात करने के कई तरीके होते हैं। उसी प्रकार से सचेत करने के भी कई तरीके होते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है। वक्त के थपेड़ों ने हमें इतना मजबूत बना दिया कि किसी भी चुनौती से निकलने में भारतीयों को मुश्किल नहीं आती। हालांकि अब तो इस वायरस की वैक्सीन भी आने वाली है। उससे पहले ही देश की रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। अगर सक्रिय केसों की बात करें तो उसके मुकाबले स्वस्थ मामले कई गुना बढ़ चुके हैं। तमाम आपात तैयारियों की जरूरत ही नहीं पड़ी है। हमारी पुरातन पद्धती ने हमारे इम्युनिटी सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया कि ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ होते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि पुरातन व्यवस्था को भूलना नहीं चाहिए। बल्कि अपने जीवन में शुमार करना चाहिए। जिंदगी तेजी के साथ पुराने ढर्रे पर लौट रही है। अर्थव्यवस्था के करीब 99 प्रतिशत क्षेत्र खोले जा चुके हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्साहित करने वाले इन नतीजों के बाद भी हम शिथिल नहीं हुए। अब जिंदगी जीने की और कोरोनाकाल हारने की ओर है। यह एक अच्छा अनुभव है। अभी कहा जा सकता है जिस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे हैं, उस तरह से कोरोना के मामलो की दर में कमी आ रही है तो आम इंसान ने कोरोना महामारी के ऊपर अपनी जीत हासिल की है। एक वक्त ऐसा हुआ कि प्रत्येक भारतीय इतना डर चुका था कि अपने जीवन को हर वक़्त डर के साथ जीता

था। हर वक्त मन में एक घबराहट थी, हालांकि ऐसी घबराहट अभी भी है जो अप्रत्याशित है कि पता नहीं अगले पल क्या होगा? हर समय एक अनजाना सा सवाल था। हर किसी की निगाहें एक दूसरे से पूछा करती थी कि आखिर कब इस कोरोना से इंसान निबट पायेगा लेकिन किसी ने सच ही कहा कि डर के आगे जीत है। जब आम जनमानस ने इस डर को निकाल फेंका और कोरोनाकाल में अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीख लिया, साथ ही साथ कोरोनावायरस को हराना भी सीख लिया और इस बात को चरितार्थ कर दिया कि डर के आगे जीत है।

बातें तो करते है लंबी चौड़ी

निगम के अफसर भी प्राइवेट बिल्डरों के आगे नतमस्तक

- वैशाली सेक्टर एक में नाले को पाट व्यक्तिगत इस्तेमाल में प्रयोग कर रहे है नामी बिल्डर
- एग्रीमेंट के अनुसार बरसात से पहले नहीं करायी जाती है नाले की सफाई
- कभी दूर नहीं होने वाली है जलभराव की समस्या
- पैसे लेकर बेचे जा रहे है शहर के नाले

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। मनोनीत पार्षद प्रदीप चौहान ने एक बयान के माध्यम से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की सैलरी वितरण में बडे घोटाले का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने कहा कि निगम सदन से तमाम कांटेक्ट वाले सफाई कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर साढे नौ हजार रूपए के भुगतान का फैसला लिया गया था, लेकिन कर्मचारियों के हाथों साढे छह हजार रूपए भी नहीं लग रहे है। श्री चौहान ने कहा कि बीच के अंतर की रकम सीएलसी का स्टाफ डकार रहा है अथवा निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपस में बंदरबाट कर रहे है, ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार मालियों को भी सैलरी के तौर पर साढे छह हजार से अधिक की रकम नहीं दी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि दुर्भाग्य पूर्ण पहलू ये है कि नगर आयुक्त पद पर जिस किसी भी अधिकारी की तैनाती की जाती है, उसके द्वारा सर्व प्रथम शहर की साफ सफाई व्यवस्था को देखा जाता है। सीधे कर्मचारियों के कंधों पर तलवार रख दी जाती है। जिस तेजी के साथ गाजियाबाद की आबादी बढ रही है उस अनुसार पांच हजार कर्मचारियों की आवश्यकता है। ढाई हजार कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। इसमें भी इन कर्मचारियों को एक दिन के अवकाश की भी सुविधा नहीं है, जबकि निगम एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अवकाश की सुविधा की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ रहे है, जबकि कर्मचारियों को एक बार मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराते हुए इतिश्री कर ली गई है। उनकी जानकारी के अनुसार शहर में चार हजार से ज्यादा हेंड पंप बेकार पडे है तथा आधे से अधिक नलकूप बेकार है। चेन्नई की जिस फर्म को सीवर व्यवस्था में सुधार का ठेका दिया गया है, वह भी औपचारिकता कर रही है, लेकिन इन तमाम हालात की तरफ किसी अधिकारी की नजर नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि यदि जलकल विभाग की फाइलों की पडताल हो तो अनेक घोटाले उजागर होंगे, लेकिन इस तरफ कोई भी देखने वाला नहीं है।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

- EVENTS MANAGEMENT
- PR MANAGEMENT
- ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक सागाचार पत्र

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, सितम्बर, 2020

कोरोना लेब बनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी

नमूना टैस्टिंग के नाम पर ढ़ाई से तीन हजार की वसूली

सफाई नायकों से लगाए बैठे है उम्मीद जो हैं अंगूठा छाप

प्रदेश में कोरोना को लेकर बिगडती स्थिति के बीच उच्च न्यायालय के कडे रूख के बाद से अब नगर निगम एवं पालिका परिषद के सफाई नायकों से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। बताते है कि 70 प्रतिशत से ज्यादा सफाई नायक अंगूठा छाप है। जो कि अपना नाम भी नहीं लिख सकते है। केवल चंद पैसे के लालच में अस्थायी एवं कांटेक्ट पर रखे गए कर्मचारियों को ही निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा सफाई नायक बना दिया गया। ये कर्मचारी मस्टरोल भी पूरा नहीं कर सकते है। सूत्र बताते है कि कांटेक्ट वाले कर्मचारियों को सफाई नायक बनाने की एवज में चार से पांच लाख रूपए तक वसूली की गई है। खेल निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया है।

- प्राइवेट लेब संचालकों से कुछ ही समय में बनाया तालमेल
- सीएमओ तक पहुंची भनक तो खुला राज

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। कोरोना के बढते मामलों को लेकर जहां केंद्र और प्रदेश सरकार चिंतित है, कोरोना के बढते मामलों पर समय रहते नियंत्रण के लिए एमएमजी अस्पताल में प्रदेश सरकार द्वारा लेब स्थापित कराते हुए करीब डेढ करोड रूपए लागत की मशीन उपलब्ध करायी गई, हैरत का पहलू ये है कि ये लेब भी अस्पताल के चंद लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है।

सूत्र बताते है कि लेब से जुडे स्टाफ के द्वारा शहर की कुछ प्राइवेट लेब के साथ तालमेल बना लिए है। प्रति सैम्पल टेस्ट के नाम पर ढाई से तीन हजार रूपए की वसूली की जा रही है। सूत्र बताते है कि चूंकि रकम का हिस्सा सीनियर अधिकारियों तक जा रहा है, जो कि जानते हुए भी अनजान बने है। मामले की भनक सीएमओ डा. एनके गुंप्ता तक पहुंची तो अब नई व्यवस्था लागू करने का फरमान जारी किया है। यहां बता दे कि जिले में तेजी से बढते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग पर शासन के द्वारा एमएमजी अस्पताल में आधुनिक लेब स्थापित करायी गई, बाकायदा डेढ करोड रूपए लागत की मशीन उपलब्ध करायी गई।

मशीन लगने के बाद प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के हाथों उदघाटन कराने की योजना तैयार की गई, लेकिन सीएम का कार्यक्रम न मिलने के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त शहर विधायक एवं योगी सरकार के स्वास्थ्यमंत्री अतुल गर्ग के हाथों उदघाटन कराया गया। बताते है कि लेब से जुडे स्टाफ के द्वारा लेब आरंभ होने के साथ ही कमाने का फंडा भी निकाल लिया गया।

बताते है कि प्राइवेट लेब के नमूने लिए जाने लगे और प्रति नमूना टैस्ट के नाम पर ढाई से तीन हजार रूपए की वसूली की जा रही थीं। बताते है कि इस खेल को सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इसी बीच पूरे खेल की भनक सीएमओ तक पहुंच गई। अब प्रत्येक नमूने से संबंधित डिटेल को एमएमजी अस्पताल परिसर में कायम नियंत्रण सेल को उपलब्ध करानी होगी।

नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सैलरी भुगतान में भी घोटाला

- सदन से प्रत्येक कर्मचारी को मिलने चाहिए साढे नौ हजार जबकि दिए जाते है मात्र साढे छह हजार
- बीजेपी पार्षद प्रदीप चौहान ने किया खुलासा
- उठाया सवाल किसकी जेब में जा रहा है पैसा

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। मनोनीत पार्षद प्रदीप चौहान ने एक बयान के माध्यम से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की सैलरी वितरण में बडे घोटाले का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने कहा कि निगम सदन से तमाम कांटेक्ट वाले सफाई कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर साढे नौ हजार रूपए के भुगतान का फैसला लिया गया था, लेकिन कर्मचारियों के हाथों साढे छह हजार रूपए भी नहीं लग रहे है। श्री चौहान ने कहा कि बीच के अंतर की रकम सीएलसी का स्टाफ डकार रहा है अथवा निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपस में बंदरबाट कर रहे है, ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार मालियों को भी सैलरी के तौर पर साढे छह हजार से अधिक की रकम नहीं दी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि दुर्भाग्य पूर्ण पहलू ये है कि नगर आयुक्त पद पर जिस किसी भी अधिकारी की तैनाती की जाती है, उसके द्वारा सर्व प्रथम शहर की साफ सफाई व्यवस्था को देखा जाता है। सीधे कर्मचारियों के कंधों पर तलवार रख दी जाती है। जिस तेजी के साथ गाजियाबाद की आबादी बढ रही है उस अनुसार पांच हजार कर्मचारियों की आवश्यकता है। ढाई हजार कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। इसमें भी इन कर्मचारियों को एक दिन के अवकाश की भी सुविधा नहीं है, जबकि निगम एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अवकाश की सुविधा की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ रहे है, जबकि कर्मचारियों को एक बार मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराते हुए इतिश्री कर ली गई है। उनकी जानकारी के अनुसार शहर में चार हजार से ज्यादा हेंड पंप बेकार पडे है तथा आधे से अधिक नलकूप बेकार है। चेन्नई की जिस फर्म को सीवर व्यवस्था में सुधार का ठेका दिया गया है, वह भी औपचारिकता कर रही है, लेकिन इन तमाम हालात की तरफ किसी अधिकारी की नजर नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि यदि जलकल विभाग की फाइलों की पडताल हो तो अनेक घोटाले उजागर होंगे, लेकिन इस तरफ कोई भी देखने वाला नहीं है।

कमीशनखोरी के चलते जांच के नाम पर काटी जा रही जेब

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। नए बस अड्डे के सामने पटेल नगर में दिवान डायग्नोस्टिक सेंटर पर कमीशनखोरी के चलते जांच कराने आने वाले मरीज की जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। इस सेंटर पर ऐसे ऐसे भी लोग आते है जो जांच कराने के लिए रकम उधार लेकर आते हैं। यह जानकारी दैनिक मनस्वी वाणी के संवाददाता को हुई तो सुनकर दिल आहत हुआ। यहां जो सीटी स्कैन 7 हजार रुपए में किया जा रहा है वही सीटी दिल्ली में करीब आधे रेटों पर हो जाता है। जबकि वरिष्ठ चिकित्सक और सूत्रों के अनुसार इस टेस्ट पर लगभग दो से ढाई हजार रुपए का मात्र खर्च आता है। इसके अलावा स्टाफ का खर्च और बिजली मगर कुल टोटल मिलाने के बाद भी 7 हजार रुपए काटने का मतलब है जनता की जेब पर डाका डालना। यानि की जो व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है उसको ऐसे हालात में दूसरों से मद्द की दरकार रहती है, किंतु भगवान के बाद पृथ्वी पर डाक्टरों को भगवान माना गया है पर यह भगवान तो मानों जैसे गडासा लेकर काटने को बैठे हो। जो व्यक्ति एक बार बीमार हो गया तो उसको तत्काल राहत देने के बजाय जब तक उसकी जेब खाली नही कर दी जाती तब तक उसको शकून नहीं देते। आलम यह हो गया है कि किसी एक दो को छोड़कर सभी का लैब और जितने भी जांच सेंटर है सबका कमीशन तय है। कमीशन खोरी के चक्कर में मरीज की खाल चिकित्सक उतार रहे है।

सिटी फॉरेस्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का भी गायब हुआ अस्तित्व

- जीडीए सचिव ने कहा सिटी फारेस्ट की जमीन पर बिल्डिंग बनाने वालों पर होगा एक्शन
- सिटी फारेस्ट की जमीन पर पांच से छह मंजिला इमारतें

–उद्योग विहार (सितम्बर 2020)–

गाजियाबाद। शासन से वृक्षारोपण का लक्ष्य मिले तो उसे पूरा करने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए हाथ खडे कर देता है। हैरत का पहलू ये है कि हापुड रोड पर विकसित की जाने वाली मधुबन बापू धाम के आस–पास जिस जमीन को सिटी फारेस्ट के लिए प्रस्तावित किया गया, मौजूदा में सिटी फारेस्ट के अस्तित्व को ही जड से समाप्त किया जा रहा है। पिछले तीन साल से सिटी फारेस्ट के लिए प्रस्तावित जमीन पर पांच से छह मंजिला इमारतों के निर्माण का खेल चल रहा है। जिन अधिकारियों पर इस अवैध निर्माण के खेल को रोकने का दायित्व है, वह शायद अनजान है, अथवा उन्हें किसी लोभ के चलते ये खेल दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो गनीमत है कि करहेडा के पास नगर निगम के द्वारा जीडीए को जमीन उपलब्ध करा दी गई और जीडीए सिटी फारेस्ट विकसित कर पाया।

पर्यावरण विद सुशील राघव कहते है कि ये बडा ही गंभीर मामला है। वैसे ही एनसीआर में बढते प्रदूषण को लेकर तमाम एजेंसियां चिंतित है। उन्होंने कहा कि जीडीए के द्वारा यदि सिटी फारेस्ट के लिए प्रस्तावित जमीन को मुक्त नहीं कराया तो एनजीटी और उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष एवं दूसरे अधिकारियों पर एक्शन की गुहार लगायी जाएगी। श्री राघव ने कहा कि जीडीए उपाध्यक्ष का भी दायित्व बनता है कि वह समय–समय पर निरीक्षण करें तथा अनियमितता आदि पाए जाने पर एक्शन ले। यहां बता दे कि हाल में भी प्रदेश शासन के द्वारा वृक्षारोपण के दिशा में गाजियाबाद जिले को लक्ष्य दिया गया, लेकिन जगह का अभाव बताते हुए जीडीए के द्वारा हाथ खडे कर दिए गए। साफ कहा गया कि वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा करने के लिए जमीन ही नहीं है। हैरत का पहलू ये है कि जीडीए के प्लानिंग विभाग के द्वारा महायोजना 2021 में मधुबन बापू धाम के एक बडे एरिया को सिटी फारेस्ट के लिए प्रस्तावित किया गया।

बताते है कि जिस मधुबन बापू धाम से लगी जमीन को सिटी फारेस्ट के लिए प्रस्तावित किया गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। बताते है कि सिटी फारेस्ट के लिए प्रस्तावित के लिए प्रस्तावित जमीन पर पांच से छह मंजिला इमारतों के निर्माण को देखा जा सकता है। हालांकि जीडीए सचिव संतोष राय बताते है कि अधीनस्थ अधिकारियों को सिटी पफारेस्ट के लिए प्रस्तावित जमीन पर अवैध निर्माण रोकने के सख्त आदेश दिए गए है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह